

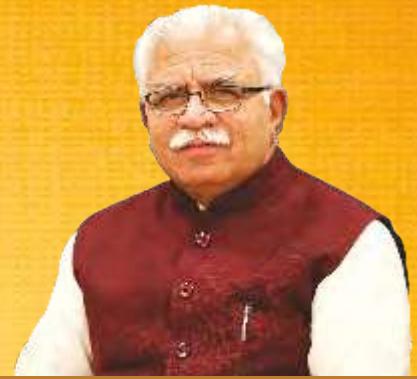
साल
हरियाणा खुशहाल

सुशासन ही आधार,
डबल इंजन हरियाणा सरकार





विराट स्वरूप, ज्योतिसर



संकल्प से परिणाम तक

शासन के कुछ मूल आधारों को छोड़कर समय के अनुसार इसमें सुधार की जरूरत सदैव बनी रहती है। मानव समाज की बदलती प्रवृत्तियों, मान्यताओं और नई आवश्यकताओं के अनुसार शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए इसमें परिवर्तन किए जाते रहे हैं। ऐसा होने पर ही यह सुशासन बन पाता है। लेकिन शासकों की मानसिकता पर यदि यथास्थितिवाद हावी हो जाए तो शासन को सुशासन बनाए रखने वाली परिवर्तन की यह धारा कुंद हो जाती है और प्रशासन में जड़ता आ जाती है। इसी के साथ शासन जनसेवा के अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है।

ऐसे ही हालात अब से 9 साल पहले हरियाणा प्रदेश के भी थे। इसलिए हमने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों के दौरान ही प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाकर इसे और अधिक उत्तरदायी बनाने का संकल्प व्यक्त किया था। हमने ऐलान किया था कि हम अपारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया तथा संसाधनों के भेदभावपूर्ण बंटवारे से दक्षता से निपटेंगे। जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला तो इस संकल्प को साकार करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना एक बड़ी चुनौती थी जो पारदर्शी, निष्पक्ष व संवेदनशील हो और जिस तंत्र में लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो।

हमने ऐसा सिस्टम बनाने का काम पहली बार शपथ लेते ही शुरू किया। एक-एक कर ऐसे सभी नियम, कानून व प्रावधान बदले जो समय प्रासंगिक नहीं रह गए थे। इससे भय, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद आदि दुष्प्रवृत्तियों पर कड़ा प्रहार हुआ। इसी समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस' की राह दिखाई और हमने इस राह पर चलते हुए सुशासन से सेवा को सुनिश्चित किया। इसी के चलते हमने वर्ष 2020 को 'सुशासन संकल्प वर्ष' और वर्ष 2021 को 'सुशासन परिणाम वर्ष' मनाया, क्योंकि हम वर्ष 2014 से जो बदलाव ला रहे थे, उनके परिणाम आने शुरू हो गए थे।

आज हमारे सुधार के संकल्प के परिणाम आ रहे हैं, अब सरकारी सेवाओं व योजनाओं के लाभ घर बैठे मिलने लगे हैं। आज प्रदेश के किसी भी नागरिक को अपना हक लेने के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। युवाओं को नौकरी व रोजगार के लिए सिफारिशें ढूँढ़ते नहीं फिरना पड़ता। सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने से लोग स्वयं इनको लागू करने में भागीदार बन रहे हैं और पूरा तंत्र एक खुली किताब की तरह पारदर्शी बन गया है।

पिछले 9 वर्ष हरियाणा में सदृभाव, सौहार्द, समाज विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ-साथ उन बदलावों के साक्षी रहे हैं, जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। व्यवस्थाएं जब घर तक पहुंचने लगती हैं, तो जीवन कैसे बदलता है, यह प्रदेशवासी अब महसूस कर ही रहे होंगे।

हमारे व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा के संकल्प के परिणामों की एक झलक इस पुस्तिका में देखने को मिलेगी।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा



श्री मनोहर लाल

मुख्यमंत्री, हरियाणा

कैबिनेट मंत्री



श्री दुष्यांत चौटाला
उप मुख्यमंत्री



श्री अनिल विज
गृह मंत्री



श्री कंवर पाल
स्कूल शिक्षा मंत्री



श्री मूलचंद शर्मा
परिवहन मंत्री



श्री रंजीत सिंह
ऊर्जा मंत्री



श्री जय प्रकाश दलाल
कृषि एवं किसान
कल्याण मंत्री



डॉ. बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री



डॉ. कमल गुप्ता
शहरी स्थानीय
निकाय मंत्री



श्री देवेन्द्र सिंह बबली
विकास एवं पंचायत मंत्री

राज्य मंत्री



श्री ओम प्रकाश यादव
सैनिक एवं अर्ध सैनिक
कल्याण, राज्य मंत्री,
स्वतंत्र प्रभार



श्रीमती कमलेश ढांडा
महिला एवं बाल विकास,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार



श्री अनूप धानक
श्रम, राज्य मंत्री,
स्वतंत्र प्रभार



सरदार संदीप सिंह
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार



संकल्प से परिणाम – 9 बड़े काम

अंत्योदय का संकल्प

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना –
27 लाख परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त अनाज
बी.पी.एल. की वार्षिक आय सीमा – ₹ 1.80 लाख
सामाजिक सुरक्षा पैशान ₹ 2,750 मासिक

पीएम जन-आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत/चिरायु)

30 लाख परिवारों को ₹ 5 लाख तक का सालाना
मुफ्त इलाज

जल जीवन मिशन

हर ग्रामीण घर (30.41 लाख) में पहुंचाया नल से जल
सौभाग्य / म्हारा गांव, जगमग गांव
5792 (86%) गांवों में 24x7 बिजली,
18,99,587 नये घरेलू बिजली कनेक्शन

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

गांवों में लाल डोरा के भीतर
25 लाख परिवारों को मालिकाना हक

परिवार पहचान पत्र

घर बैठे 45 लाख परिवारों ने उठाया 397 योजनाओं व
सेवाओं का लाभ

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

जन्म के समय लिंगानुपात 871 (वर्ष 2014)
और अब सुधर कर 932 (सितम्बर, 2023)

पी.एम. किसान योजना

19.5 लाख किसानों के खातों में ₹ 4,645 करोड़ का अनुदान
मेरी फसल, मेरा व्यौरा
12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के
₹ 85 हजार करोड़ सीधे रक्षानांतरित

E-learning को बढ़ावा

सरकारी स्कूलों के बच्चों को
5.50 लाख टेबलेट्स वितरित

राज्य का हर जिला नेशनल हाइवे से जुड़ा,
हिसार व अंबाला में दो नये नागरिक हवाई अड्डे

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सबतै आग्ने म्हारा हरियाणा	01-02
2.	हरियाणा की प्रगति का ब्यौरा	03-04
3.	परिवार पहचान पत्र	05-06
4.	व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन	07-08
5.	अंत्योदय- वंचित को दिया उनका हक	09-10
6.	बीज से बाजार तक किसान के साथ खड़ी सरकार	11-12
7.	ग्राम विकास	13-14
8.	स्वावलंबी स्थानीय निकाय एवं शहरी विकास	15-16
9.	ऊर्जा	17-18
10.	नारी सशक्तिकरण	19-20
11.	श्रमिक कल्याण	21-22
12.	शिक्षा से रोजगार	23-24
13.	सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं	25-26

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
14.	युवा प्रदेश की शक्ति	27-28
15.	इंफ्रास्ट्रक्चर विकास	29-30
16.	उद्योग एवं व्यापार	31-32
17.	परिवहन	33-34
18.	हरियाणा- स्पोर्ट्स का पावर हाउस	35-36
19.	कानून व्यवस्था	37-38
20.	सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण	39-40
21.	कर्मचारियों को सुविधाएं	41-42
22.	संस्कृति एवं पुरातत्व	43-44
23.	वन एवं पर्यावरण संरक्षण	45-46
24.	हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों, आपातकालीन पीड़ितों व पत्रकारों को सुविधाएं	47-48
25.	नए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान	49
26.	बदले गये गांवों के नामों की सूची	50



सबतै आगै म्हारा हरियाणा

पढ़ी-लिखी पंचायतों वाला देश का एकमात्र राज्य
महिलाओं को पंचायतों में **50 प्रतिशत भागीदारी**

न खर्ची, न पर्ची
योग्यता के आधार पर 1 लाख 10 हजार सरकारी नौकरियां,
60,000 पदों पर भर्ती शीघ्र

सी.एम. विंडो
11 लाख जन-शिकायतों का पारदर्शिता से समाधान

प्रति व्यक्ति वार्षिक आय
₹2,96,685, बड़े राज्यों में सर्वाधिक

मनरेगा
दैनिक मजदूरी ₹357, देश में सर्वाधिक

एम.एस.पी. पर **14 फसलों** की
खरीद करने वाला पहला राज्य

मेरा पानी, मेरी विरासत- पानी बचाने के लिए
71,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसल

पी.एम. कुसुम योजना
देश में सर्वाधिक 62,578 सोलर पंप स्थापित
तथा 70,000 नये पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू

डायल 112 - 20 लाख आपातकालीन कॉल्स पर
औसतन 8 मिनट में सहायता

हर जिले में **महिला पुलिस थाना** तथा
साइबर अपराध थाना स्थापित

ऑटो अपील सिस्टम
राइट टू सर्विस एक्ट को सही मायने में लागू किया,
9 लाख शिकायतों का ऑटोमेटिक समाधान

अंत्योदय सरल पोर्टल - 54 विभागों की 675 योजनाएं
ऑनलाइन, 10 करोड़ से अधिक सेवाएं प्रदान कीं

निरोगी हरियाणा - 32 लाख से अधिक पात्र
परिवारों के लगभग 1.77 करोड़ मुफ्त टेस्ट

हर जिले में मेडिकल कॉलेज
मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 15
MBBS सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2185

विवाह शगुन योजना - पात्र परिवारों की बेटियों की
शादी पर ₹71,000 तक का शगुन

हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों तथा
आपातकालीन पीड़ितों व विधवाओं को सम्मान व मासिक पेंशन

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ... बेमिसाल
NCR क्षेत्र में बिछा मैट्रो का जाल
₹5618 करोड़ की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर
₹70 हजार करोड़ की लागत से क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (नमो भारत ट्रेन) पर काम शुरू



हरियाणा की प्रगति का व्यौरा

विवरण	1966–67	2014–15	2023–24
प्रति व्यक्ति आय (रुपये)	608	1,37,770	2,96,685
प्रदेश का निर्यात (करोड़ रुपये)	4.50	68,032	2,45,453 <small>(2022-2023)</small>
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	25.92	169.74	185.05
दुग्ध उत्पादन (लाख टन)	10.89	79.01	116.19
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता (ग्राम)	357	747	1081
चीनी मिल्स	2	11	14
महाविद्यालयों की संख्या	45	105	182
विश्वविद्यालयों की संख्या	1	43	56
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	60	142	192
मेडिकल कॉलेजों की संख्या	1	7	15
स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या	797	3944	4266
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च (रुपये)	1.90	1043	2109
बिजली उपभोक्ता (लाख)	3.12	54.91	76.65
पक्की सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर)	5100	23,548	28,077



परिवार पहचान पत्र

- नागरिकों को दफ्तर, दस्तावेज व दरखास्त से मुक्ति।
- इस एक ही पत्र से सभी योजनाओं का लाभ घर बैठे, **71** लाख परिवारों के **2.83** करोड़ सदस्यों का डेटा हुआ अपडेट।
- पी.पी.पी. से **397** सेवाओं व योजनाओं को जोड़ा गया, **45** लाख परिवारों ने लाभ उठाया।
- 1.40 लाख वृद्धजनों तथा 14 हजार दिव्यांगजनों को घर बैठे पेंशन का लाभ।
- ऑटोमेटिकली घर बैठे बने **39** लाख बी.पी.एल. राशन कार्ड तथा **57** लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड।
- निरोगी हरियाणा योजना – 32 लाख से अधिक गरीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच।
- मुख्यमंत्री विवाह शुगुन योजना का लाभ घर बैठे सीधा खाते में।
- जाति एवं आय प्रमाण-पत्र ऑनलाइन घर बैठे।





व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन

- सुशासन की नई पहलों से प्रदेश के नागरिकों में यह भावना पैदा हुई है कि सरकार उनकी है और वे सरकार में हैं।
- अंत्योदय सरल पोर्टल - 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन।
- सी.एम. विंडो - 11 लाख शिकायतों का समाधान।
- डी.बी.टी. - 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली अथवा दोहरे लाभार्थियों को हटाया, जिससे रीयल टाइम बचत 1182.23 करोड़ रुपये।
- ऑटो अपील सॉफ्टवेयर - इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन तथा 9 लाख शिकायतों का निपटान।
- हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा 112 - 20 लाख कॉल्स का समाधान।
- ई-ऑफिस - सरकारी कामकाज में तेजी।





17 सितम्बर 2023 - लखनऊ

सूचना, जन सभा वार्षिक आषा तथा

अंत्योदय-वंचित को दिया उनका हक

योजनाएँ	अक्टूबर, 2014	अक्टूबर, 2023
बी.पी.एल की वार्षिक आय सीमा	► 1.20 लाख रुपये	► 1.80 लाख रुपये
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	► 1000 रुपये मासिक	► 2750 रुपये मासिक
सामाजिक सुरक्षा की वार्षिक आय सीमा	► 2 लाख रुपये	► 3 लाख रुपये
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी	► 21.82 लाख	► 30.34 लाख
बेटियों की शादी पर शागुन राशि	► 31,000 रुपये तक	► 71,000 रुपये तक
बी.पी.एल. परिवारों को मकान मरम्मत के लिए सहायता राशि	► 25,000 रुपये	► 80,000 रुपये

- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना - सबसे गरीब 50 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण।
- आयुष्मान भारत-चिरायु योजना - 86 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए, 8.50 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपये के क्लोम दिये। अब इसमें 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार भी 1500 रुपये वार्षिक अंशदान पर शामिल।
- निरोगी हरियाणा योजना - 32 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच व 1.77 करोड़ टेस्ट निःशुल्क किये गये।
- प्रधानमंत्री आवास योजना - 43,201 लोगों को अपना घर मिला, 16 हजार मकान निर्माणाधीन, 926.44 करोड़ रुपये की अनुदान राशि लाभार्थियों को वितरित।
- दयालु योजना - 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता।
- मुख्यमंत्री विवाह शागुन योजना - 2.58 लाख गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 821 करोड़ रुपये का शागुन।
- आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना - अंत्योदय परिवारों की 4.47 लाख लड़कियों को जन्म पर 21,000 रुपये प्रति बेटी।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना - 79,007 रेहड़ी-फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - 27 लाख परिवारों को दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त राशन।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - गरीब परिवारों को 9.54 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन।



बीज से बाजार तक किसान के साथ खड़ी सरकार

योजनाएं	अक्टूबर, 2014	अक्टूबर, 2023
प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर प्रति एकड़ मुआवजा	10,000 रुपये तक	15,000 रुपये तक
प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर कुल मुआवजा	1158 करोड़ रुपये (पिछली सरकार में)	11,000 करोड़ रुपये (वर्तमान सरकार में)
गन्ने का भाव प्रति विचंटल	310 रुपये	372 रुपये
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता	747 ग्राम	1081 ग्राम (2021-22)
सुक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र	33,507 हैक्टेयर	4,26,636 हैक्टेयर
प्राकृतिक आपदा से मानव मृत्यु पर राहत राशि	2 लाख रुपये	4 लाख रुपये
मत्स्य उत्पादन	1 लाख मीट्रिक टन	2 लाख मीट्रिक टन

- एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
- मेरी फसल-मेरा ब्लौरा पोर्टल- 12 लाख किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में सीधे 85,000 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना- 19.50 लाख किसानों के खातों में 4645 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- 27.22 लाख किसानों को 7600 करोड़ रुपये के बीमा क्लोम।
- मेरा पानी-मेरी विरासत योजना- 71,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोई, 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 118 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- भावांतर भरपाई योजना-बाजरा व बागवानी किसानों के खातों में 750 करोड़ रुपये डाले।
- गन्नौर (सोनीपत) में 7,000 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट निर्माणाधीन।
- दक्षिण हरियाणा के माईनरों में 39 वर्ष बाद तथा सभी टेलों तक पहुंचा पानी।
- अमृत सरोवर मिशन-1661 तालाबों का जीर्णोद्धार।



ग्राम विकास

योजनाएं	अक्तूबर, 2014	अक्तूबर, 2023
मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन	214 रुपये	357 रुपये
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय	8,100 रुपये	14,000 रुपये
ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय	3,500 रुपये	11,000 रुपये
नम्बरदारों का मासिक मानदेय	1,500 रुपये	3,000 रुपये
ग्राम पंचायत के सदस्यों का मासिक मानदेय	2,000 रुपये तक	5,000 रुपये तक
पंचायत समिति के सदस्यों का मासिक मानदेय	6,000 रुपये तक	7,500 रुपये तक
जिला परिषद् के सदस्यों का मासिक मानदेय	7,500 रुपये तक	10,000 रुपये तक

- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना- 6,260 गांवों में लाल डोरे के भीतर 25.17 लाख प्राप्ती कार्ड बनाए।
- हर घर नल से जल योजना- सभी 6,803 गांवों के 30.41 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध।
- हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का पहला राज्य।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी।
- पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘ए’ को 8 प्रतिशत आरक्षण।
- आई.टी. युक्त ग्राम सचिवालय योजना- 1856 ग्राम सचिवालयों की स्थापना।



स्वावलंबी स्थानीय निकाय एवं शहरी विकास

योजना	अक्तूबर-2014	अक्तूबर, 2023
अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित	874	2547

- शहरी स्वामित्व योजना - 20 साल से अधिक समय से काबिज व्यक्तियों का किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत।
- मेयर या अध्यक्ष का सीधे ही चुनाव।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए सम्पत्ति के पंजीकरण पर 2 प्रतिशत राजस्व।
- शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गुरुग्राम, पंचकूला, सोनीपत व फरीदाबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अॉरिटी का गठन।
- बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने तथा अलॉटियों को समय पर कब्जा दिलवाने हेतु हरियाणा रियल एस्टेट ऑरिटी गुरुग्राम व पंचकूला में स्थापित।





ऊर्जा

योजनाएं	अक्टूबर, 2014	अक्टूबर, 2023
24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांवों की संख्या	538	5,792
24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले जिलों की संख्या	शून्य	11
बिजली लाईन लॉस (गांवों में)	80 प्रतिशत तक	13.60 प्रतिशत
बिजली बिलों की रिकवरी (गांवों में)	50 प्रतिशत तक	84.26 प्रतिशत

- प्रधानमंत्री कुसुम योजना - 62,578 सोलर पंप स्थापित तथा 70,000 नये सोलर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू।
- उजाला योजना - 1.56 करोड़ LED बल्ब, 2.13 लाख LED ट्रूब तथा 60,709 पंखे वितरित, जिनसे 411 मेगावाट ऊर्जा की वार्षिक बचत।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,92,456 नये ट्रांसफार्मर लगाये गये।
- 51,886 किसानों को नलकूप कनेक्शन दिये गए।
- 18,99,587 नये घरेलू बिजली कनेक्शन दिये गए।
- घरों, कॉलोनियों, तालाबों तथा स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली 3,151 खतरनाक लाईनों में से 3,143 लाईनों को हटाया गया।





नारी सशक्तिकरण

योजनाएं	अक्तूबर, 2014	अक्तूबर, 2023
जन्म के समय लिंगानुपात की दर	871	932 (सितम्बर, 2023)
महिला पुलिस थाने	2	33
राजकीय महिला कॉलेज	29	61
विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की मासिक पेंशन	1000 रुपये	2750 रुपये
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय	7,500 रुपये	12,661 रुपये
आशा वर्कर्स का मासिक मानदेय	500 रुपये	6100 रुपये

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को एकमुश्त 6000 रुपये तक, 7.88 लाख लाभपात्रों को 342 करोड़ रुपये की राशि दी गई।
- हरिहर योजना - बाल देख-रेख गृहों में रह रहे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनाथ बच्चों को 2750 रुपये मासिक वित्तीय सहायता।
- प्ले-वे स्कूल - 4000 आंगनवाड़ी प्ले-वे स्कूलों में 40 हजार बच्चे लाभांवित, इनके अलावा 4000 नए प्ले-वे स्कूल खोलने का निर्णय।
- छात्राओं के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।
- 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को।



श्रमिक कल्याण

योजनाएँ	अक्टूबर, 2014	अक्टूबर, 2023
अकुशल श्रमिकों को मासिक न्यूनतम वेतन	► 5639.50 रुपये	► 10661.28 रुपये
उच्च कुशल श्रमिकों को मासिक न्यूनतम वेतन	► 6289.50 रुपये	► 13606.75 रुपये
पंजीकृत श्रमिकों की बेटी की शादी में शागुन राशि	► 51,000 रुपये	► 1,01,000 रुपये

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना- 18 से 40 वर्ष की आयु वाले असंगठित श्रमिकों को आयु के अनुसार मासिक योगदान पर 60 वर्ष की आयु के उपरांत 3,000 रुपये की मासिक पेंशन।
- बच्चों की शिक्षा के लिए स्नातक कक्षा तक 20 हजार रुपये वार्षिक तक आर्थिक सहायता।
- पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को दसवीं एवं 12वीं कक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि।





शिक्षा से रोजगार

योजनाएं	अक्तूबर, 2014	अक्तूबर, 2023
विश्वविद्यालय	► 43	► 56
राजकीय महाविद्यालय	► 105	► 182
राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति विद्यालय	► 13	► 147
प्राइमरी राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय	► शून्य	► 1419

- वर्ष 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य।
- अध्यापकों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू की गई, देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं।
- ई-अधिगम योजना- सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 5.50 लाख टेबलेट्स निःशुल्क वितरित, बच्चे अब सुनने के साथ करके भी सीखेंगे।
- चिराग योजना- 2650 गरीब परिवारों के बच्चों का मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिला।
- बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए पहली से तीसरी कक्षा तक Functional Literacy & Numeracy (FLN) कार्यक्रम शुरू।
- दुधोला (पलवल) में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित।
- KG से PG तक 4 विश्वविद्यालयों में दाखिले।
- हिन्दी भाषा में बी.टेक पाठ्यक्रम 3 विश्वविद्यालयों में शुरू।



सरके लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं

योजनाएं	अक्तूबर, 2014	अक्तूबर, 2023
मेडिकल विश्वविद्यालय	1	2
मेडिकल कॉलेजों की संख्या	6	15
मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या	700	2185
मेडिकल कॉलेजों में P.G. सीटों की संख्या	289	1006
नागरिक अस्पतालों की संख्या	56	72
अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए पी.एस.ए. प्लांट	शून्य	94
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स	शून्य	2700

- आयुष्मान भारत-चिरायु योजना - 86 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए, 8.50 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपये के क्लोम दिये। अब इसमें 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार भी 1500 रुपये वार्षिक अंशदान पर शामिल।
- देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित।
- अम्बाला सिविल अस्पताल, अम्बाला छावनी में कैंसर के इलाज के लिए अटल कैंसर केयर सेंटर शुरू।
- 17 जिला सिविल अस्पतालों में सी.टी. स्कैन, 22 सिविल अस्पतालों में हैमोडायलिसिस, 5 जिला सिविल अस्पतालों में एम.आर.आई. और 4 केंद्रों पर कार्डियोलॉजी सेवाएं शुरू।
- ई-संजीवनी ओ.पी.डी. द्वारा लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध।
- 13 सिविल अस्पतालों को 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों से 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों में और अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तरों वाले अस्पताल से 300 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया गया।



युवा प्रदेश की शक्ति

- पारदर्शिता एवं मैरिट के आधार पर **1.10 लाख** युवाओं को सरकारी नौकरी, 60 हजार पदों पर भर्ती जल्द।
- भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त।
- बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से छुटकारे के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान।
- उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण।
- सक्षम युवा योजना- 4 लाख सक्षम युवाओं को 9,000 रुपये प्रतिमाह तक, 2,577 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता व मानदेय के रूप में वितरित।
- बेरोजगारी भत्ता योजना- 12वीं, स्नातक व समकक्ष युवाओं को 3,000 रुपये मासिक तक बेरोजगारी भत्ता, 32,361 लाभार्थियों को 208 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित।
- हरियाणा कौशल विकास मिशन-1 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण।
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा समाप्त की।





इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

- प्रदेश का हर जिला जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग से, 8 का कार्य पूर्ण व 12 का प्रगति पर।
- दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुण्डली-मानेसर-पलवल और कुण्डली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे पर यातायात शुरू।
- अम्बाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (152-डी) 10,646 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण।
- हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बनाया, अम्बाला हवाई अड्डे का निर्माण जल्द।
- रोहतक शहर में देश की पहली एलिवेटिड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण एवं कुरुक्षेत्र में शुरू।
- 2577 करोड़ रुपये की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 50 पुलों का कार्य प्रगति पर।
- वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़, बहादुरगढ़-मुंडका (दिल्ली), बदरपुर-मुजेसर (वाई.एम.सी.ए. चौक) व सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर-56 तक मैट्रो रेल सेवा शुरू।

पेयजल व अन्य सुविधाएं

- प्रदेश के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया।
- ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी- गैर पीने योग्य 200 लाख लीटर उपचारित जल का प्रतिदिन उपयोग।



उद्योग एवं व्यापार

- प्रदेश का निर्यात 68,032 करोड़ रुपये (वर्ष 2014) से बढ़कर 2,45,453 करोड़ रुपये (वर्ष 2022-23) हुआ।
- 18,422 करोड़ रुपये के निवेश से 1,59,622 उद्योग लगे तथा **12.60** लाख लोगों को रोजगार।
- नारनौल में 700 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब।
- आई.एम.टी. खरखौदा (सोनीपत) में मारुति सुजुकी द्वारा 800 एकड़ तथा सुजुकी द्वारा 100 एकड़ भूमि पर उद्योग।
- पी.एम. गति शक्ति योजना- 6 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं मंजूर।
- पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क व हिसार में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित।
- पदमा स्कीम (वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट) के तहत 143 ब्लॉकों में क्लस्टर आधार पर प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स में विकास शुरू।

व्यापारियों को सुविधाएं

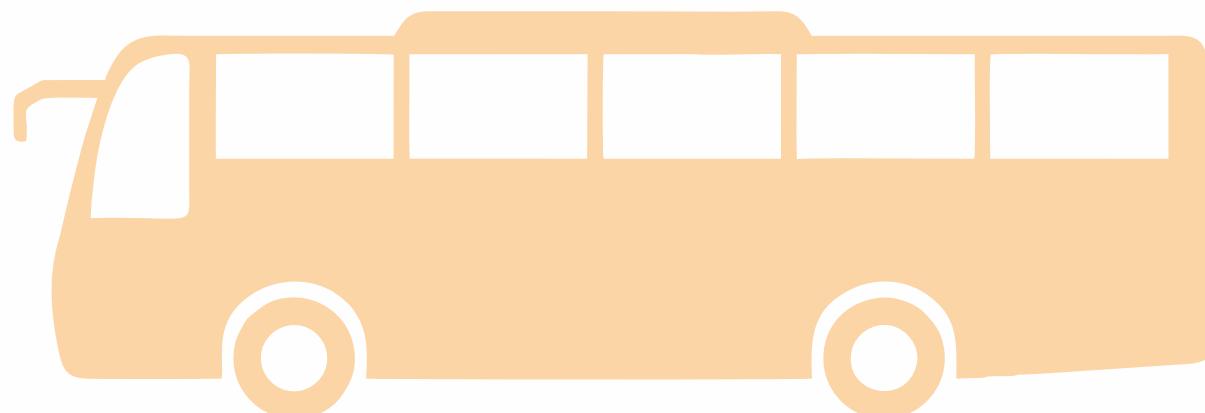
- संशोधित मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना- आग और सेंधमारी के मामले में नुकसान के लिए 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर।
- मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना- 3.86 लाख पंजीकृत व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान।





परिवहन

- माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्वौपदी मुर्मु जी द्वारा सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं में देश में सर्वप्रथम ई-टिकटिंग का शुभारम्भ।
- प्रदेश के सभी बस अड्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गए।
- चालक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 22, जिनमें 2,69,408 नये भारी वाहन चालक प्रार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।





हरियाणा- स्पोर्ट्स का पावर हाउस

योजनाएं	अक्तूबर-2014	अक्तूबर, 2023
ओलम्पिक व पैरालम्पिक पदक विजेताओं को सम्मान राशि	5 करोड़ रुपये	6 करोड़ रुपये
एशियन व पैराएशियन पदक विजेताओं को सम्मान राशि	2 करोड़ रुपये	3 करोड़ रुपये
कॉमनवेल्थ पदक विजेताओं को सम्मान राशि	1 करोड़ रुपये	1.50 करोड़ रुपये
खिलाड़ियों को नौकरी	41	216

- पदक विजेता खिलाड़ियों को देश में सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि।
- पदक विजेता खिलाड़ियों को 419 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गये।
- खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित, क्लास वन से क्लास फौर तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण।
- राई (सोनीपत) में हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

हरियाणा ने देश की झोली मेडलों से भर दी

स्पर्धा	भारत	हरियाणा
ओलम्पिक खेल-2016	2	1
ओलम्पिक खेल-2020	7	4
कुल	9	5
पैरालम्पिक-खेल 2016	4	1
पैरालम्पिक खेल-2020	19	6
कुल	23	7
एशियन खेल-2018	70	17
एशियन खेल-2022	107	30
कुल	177	47



कानून व्यवस्था

- डायल-112 द्वारा 20 लाख आपातकालीन त्वरित सहायता औसतन 8 मिनट में।
- पंचकूला पुलिस मुख्यालय पर हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित।
- 31 महिला पुलिस थाने तथा 200 महिला हेल्प डेस्क स्थापित।
- साइबर अपराधों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए गुरुग्राम में देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर **DIATAC** स्थापित।
- जिला स्तर पर कुल 29 साइबर अपराध पुलिस थाने व 318 साइबर डेस्क स्थापित।

बस एक कॉल दूर

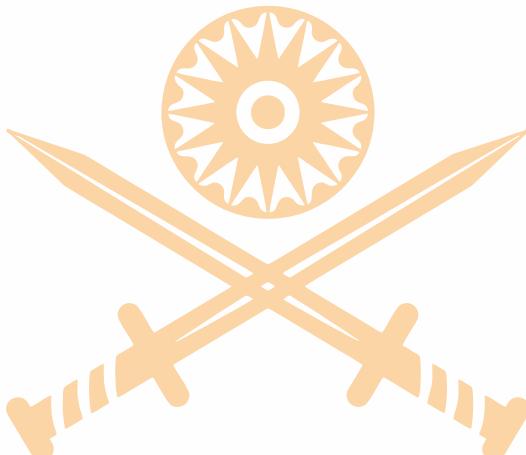




सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण

योजनाएँ	अक्तूबर-2014	अक्तूबर, 2023
शहीद सैनिक अनुग्रह अनुदान राशि	► 20 लाख रुपये	► 50 लाख रुपये
घायल सैनिकों के लिए निःशक्तिता के आधार पर अनुग्रह राशि	► 15 लाख रुपये तक	► 35 लाख रुपये तक
अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों की संख्या	► 6	► 367

- भूतपूर्व सैनिक व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कल्याण के लिए सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग गठित।
- सैनिक एवं अर्ध सैनिक के आश्रितों के लिए मुफ्त कोचिंग।
- वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा।





कर्मचारियों को सुविधाएं

- सातवें वेतन आयोग को सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
- नई एक्सग्रेशिया स्कीम - सरकारी कर्मचारी के 52 साल की उम्र से पहले निधन होने पर आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नौकरी का प्रावधान।
- ऑउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समकक्ष मातृत्व अवकाश की सुविधा।
- नगरपालिका के सफाईकर्मियों का **10 लाख रुपये का बीमा**।
- दिव्यांग महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए 1,500 रुपये प्रति बच्चा विशेष भत्ता।
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति।





संरकृति एवं पुरातत्व

- मॉरीशस, लंदन, कनाडा और आस्ट्रेलिया में अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन।
- स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन योजना- 10,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री वार्षिक वित्तीय सहायता।
- कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना- 50,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री वार्षिक वित्तीय सहायता।
- राखीगढ़ी, हिसार में 6 एकड़ क्षेत्र में संग्रहालय एवं विवेचन केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी।
- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम-1857 के शहीदों के सम्मान में अम्बाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीदी स्मारक।
- गुरुग्राम और नूंह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय अरावली सफारी पार्क को विकसित करने का निर्णय।

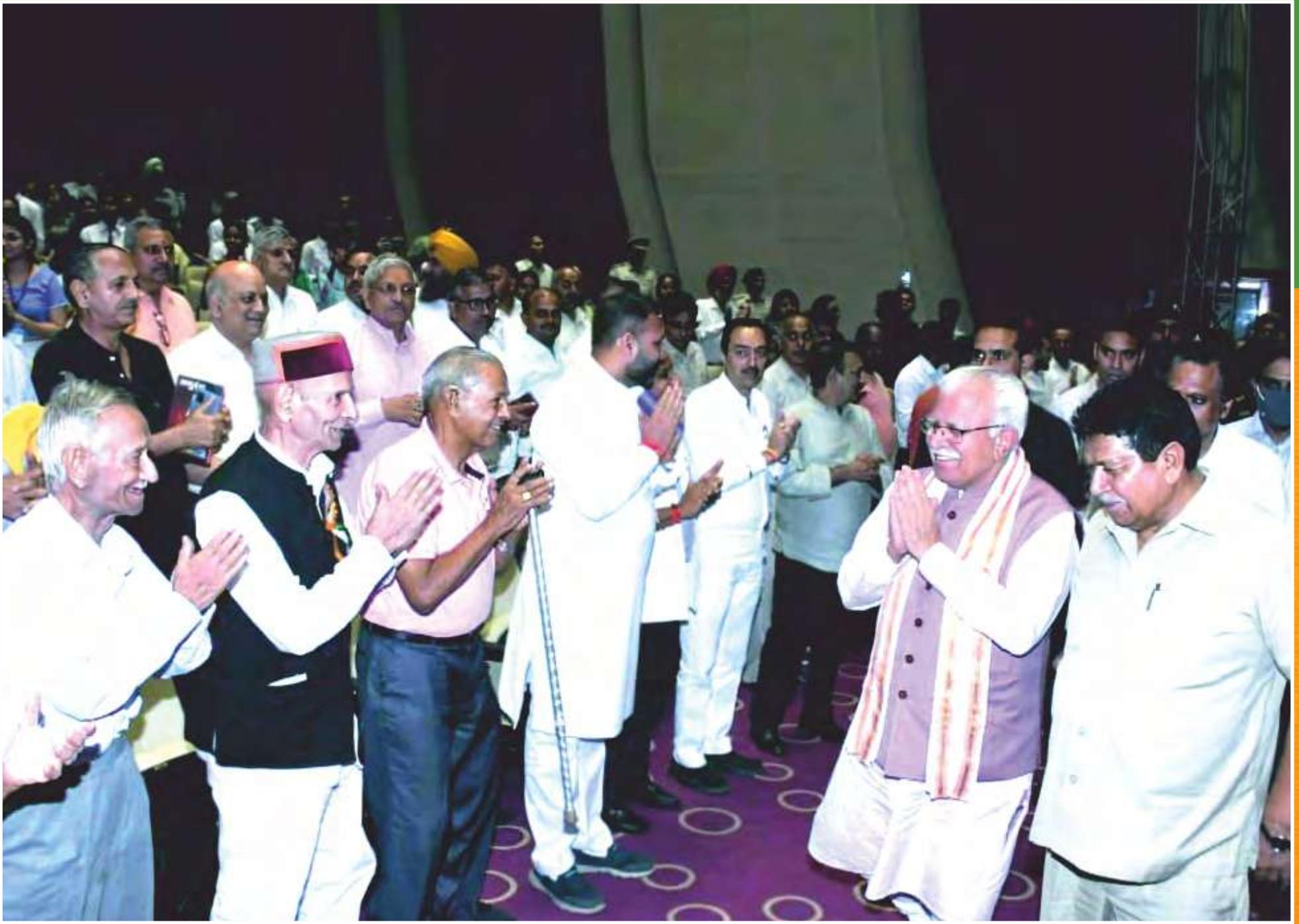


वन एवं पर्यावरण संरक्षण

- प्राणवायु देवता पेंशन योजना - 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए 2500 रुपये वार्षिक।
- ऑक्सीवन योजना- 34 ऑक्सीवन स्थापित किए जा रहे हैं, पंचकूला व करनाल में ऑक्सीवन की स्थापना।
- प्रदेश में 62 हर्बल पार्क विकसित किये।

जल संरक्षण

- जल बचाओ-कल बचाओ योजना - 200 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के पानी का पावर प्लांट्स व उद्योगों में उपयोग।
- Haryana Water Resources Authority, **MICADA** और **Haryana Pond and Waste Water Management Authority** का गठन।
- दो **Wet Land**-सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम व भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, झज्जर को रामसर साइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली।
- मुरथल (सोनीपत) में 177 करोड़ रुपये की लागत से कूड़े-कचरे से बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित।



हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों को सुविधाएं

- हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन।
- आपातकालीन पीड़ितों व विधवाओं को सम्मान एवं 10,000 रुपये मासिक पेंशन।

पत्रकारों को सुविधाएं

- पत्रकारों को 15,000 रुपये मासिक पेंशन।
- सभी मीडियाकर्मियों को जीवन बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक जीवन बीमा लाभ।
- कैशलेस मेडिकल चिकित्सा सुविधा जल्द।

नए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान

क्रमांक	संस्थान का नाम	स्थान
1.	भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)	सुनारिया, रोहतक
2.	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIEIT)	कुरुक्षेत्र
3.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID)	उमरी, कुरुक्षेत्र
4.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET)	मुख्थल, सोनीपत
5.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT)	पंचकूला
6.	आई.आई.टी दिल्ली विस्तार केंद्र	सोनीपत
7.	राष्ट्रीय कैंसर संस्थान	बाढ़सा, जिला झज्जर
8.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान	पंचकूला
9.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)	रेवाड़ी (प्रस्तावित)

गांवों के बदले गये नामों की सूची

क्रमांक	गांव का पुराना नाम	गांव का नया नाम	अधिसूचना की तिथि
1.	जिला सिरसा – गांव संघर सरिता	बाबा भूमण शाह	26.06.2015
2.	जिला यमुनानगर – गांव मुस्ताफाबाद	सरस्वती नगर	02.02.2016
3.	जिला गुडगांव – गुडगांव शहर	गुरुग्राम	14.10.2016
4.	जिला फतेहाबाद – गांव गन्दा	अजीत नगर	04.07.2017
5.	जिला हिसार – गांव किन्नर	गैबी नगर	25.07.2017
6.	जिला महेन्द्रगढ़ – गांव चामघेड़ा	देव नगर	31.08.2017
7.	जिला रोहतक – गांव गढ़ी सांपला	चौ. सर छोटूराम नगर	09.11.2017
8.	जिला जीन्द – गांव पिण्डारी	पाण्डू-पिण्डारा	28.02.2018
9.	जिला जीन्द – गांव टोडी खेड़ी	सरना खेड़ी	30.10.2018
10.	जिला यमुनानगर – गांव खिजराबाद	प्रताप नगर	28.12.2018
11.	जिला रेवाड़ी – गांव लूला अहीर	कृष्ण नगर	05.08.2019
12.	जिला करनाल – गांव बाल रागडान	बाल राजपुतान	05.08.2019
13.	जिला हिसार – गांव कुतिया खेड़ी	वीरपुर	05.08.2019
14.	जिला करनाल – गांव लण्डौरा	जयरामपुर	20.08.2019
15.	जिला कुरुक्षेत्र – गांव अमीन	अभिमन्यूपुर	16.01.2020
16.	जिला जीन्द – गांव गैण्डा खेड़ी	गुरुकुल खेड़ा	10.07.2020
17.	जिला गुरुग्राम – मोहम्दहेड़ी	ब्रह्मपुरी	25.08.2023

નોટસ





९ वर्षों की यही पहचान विकसित हरियाणा, जन जन का सम्मान